

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 282] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941 [N.C.T.D. No. 254

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सं. 07/2019-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(74)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/498.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त नीचे तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता के रूप में विलोमतः प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, यथा:-

तालिका

क्र.सं.	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति [डिबलपमेंट राइट्स के अनुदान, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास शुल्क आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के	प्रोमोटर

	प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा] अधिसूचना सं०. 11/2017-राज्य कर, दिनांक 30.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सं० फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30.06.2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ik), (ix), (ig) और (घ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	
2	सीमेन्ट जो कि सीमाशुल्क टैरिक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है जो कि अधिसूचना सं०. 11/2017-राज्य कर, दिनांक 30.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सं० फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30.06.2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ik), (ix), (ig) और (घ) में यथा निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष (या पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग या पहले व्यवसाय, जो भी पहले हो, तक) में, जो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य से कमी को संस्थापित करता है।	प्रमोटर
3	पूँजीगत माल जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आता हो और जिसे ऐसे किसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किसी प्रमोटर को आपूर्ति किया गया हो जिस पर अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर, दिनांक 30.06.2017, यथा संशोधित, जिसे सं० फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30.06.2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया है, के क्रम सं. 3 के समक्ष के मद (i), (ik), (ix), (ig) और (घ) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान देय हो या किया जाता हो।	प्रमोटर

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, -

(i) “प्रमोटर” शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ii) “प्रोजेक्ट” से अभिप्राय: किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R E P) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R R E P) से है

(iii) रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R E P) का वही अभिप्राय: होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(iv) “रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)” का अभिप्राय: उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(v) "फ्लोर स्पेस इंडेक्स (फसआई)" से अभिप्राय: किसी भवन के कुल फ्लोर क्षेत्रफल (सम्पूर्ण फ्लोर क्षेत्रफल) और उस भू-खंड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
के. सिंह, उप सचिव

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd October, 2019

No. 07/2019-State Tax (Rate)

No. F.3 (74)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/498.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person specified in column (3) of the table below, shall in respect of supply of goods or services or both specified in column (2) of the Table below, received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods or services or both, namely:—

TABLE

Sl. No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
1	Supply of such goods and services or both [other than services by way of grant of development rights, long term lease of land (against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc.) or FSI (including additional FSI)] which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 30 th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Gazette of Delhi vide number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30 th June, 2017, as amended.	Promoter.
2	Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 30 th June, 2017, at items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial No. (3), published in Gazette of Delhi vide number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 381, dated the 30 th June, 2017, as amended.	Promoter.

3	Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed for items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) against serial number 3 in the Table, in notification No. 11/ 2017- State Tax (Rate), dated 30 th June, 2017, published in Gazette of Delhi <i>vide</i> number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30 th June, 2017, as amended.	Promoter
---	--	----------

Explanation. - For the purpose of this notification, -

- (i) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (ii) “project” shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
- (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (iv) “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.
- (v) the term “floor space index (FSI)” shall mean the ratio of a building’s total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of April, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.